देशव्यापी औद्योगिक हड़ताल के लिए तैयारी करो

पी. के. गांगुली

सीटू वर्किंग कमेटी ने नरसिंह राव सरकार के आर्थिक कदमों के खिलाफ, जिनसे देश की आर्थिक संप्रभुता आइ एम एफ तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथों बेचे जाने का खतरा पैदा हो गया है, एक दिन की देशव्यापी औद्योगिक हड़ताल की तैयारी करने का जोरदार आह्वान किया है। वर्किंग कमेटी की बैठक 1 से 3 सितम्बर तक नयी दिल्ली में हुई।

बैठक ने ऐसी कार्रवाई की दिशा में अनेक केंद्रीय ट्रेड यूनियनों तथा राष्ट्रीय औद्योगिक फेडरेशनों की 13 अगस्त को दिल्ली में संपन्न बैठक की पहल का स्वागत किया। व्यापक आधार वाली इस बैठक में इस कार्रवाई के लिए एक आयोजन समिति का गठन किया गया। इसके साथ 17 सितम्बर को दिल्ली में एक राष्ट्रीय कन्वेंशन के आयोजन का भी फैसला लिया गया है, जिसकी ओर से हड़ताल का आह्वान किया जायगा।

सीटू वर्किंग कमेटी ने सभी ट्रेड यूनियनों का और मेहनतकश जनता के सभी हिस्सों का, चाहे वे निजी क्षेत्र के मजदूर हों या सार्वजनिक क्षेत्र के, केंद्र सरकार के कर्मचारी हों या राज्य सरकार के, आह्वान किया है कि इस जबर्दस्त देशव्यापी हड़ताल में अपनी सांगठनिक तथा राजनीतिक वफादारियों से ऊपर उठकर हिस्सा लें। उसने, जनता के सभी देशभक्तों जनतंत्र में यकीन रखने वालों से और इन आर्थिक नीतियों की मार में आये सभी लोगों से भी अपील की है कि देश की आर्थिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के हक में इस आंदोलन को अपना समर्थन दें।

वर्किंग कमेटी ने इस पर संतोष के साथ गौर किया कि सीटू की राज्य कमेटियों ने इस सिलसिले में तैयारियों तथा अभियान की शुरूआत भी कर दी और पश्चिम बंगाल में इस सिलसिले में बीस हजार लोगों की विशाल जन-कन्वेंशन आयोजित की गयी है। सीटू वर्किंग कमेटी ने आयोजन समिति से अपील की कि जल्द से जल्द हड़ताल की तारीख तय करे, जिसका एलान कन्वेंशन में किया जाना है।

अध्यक्षीय भाषण

हालात के तकाजों को देखते हुए वर्किंग कमेटी की इस बैठक में 121 की रिकार्ड संख्या में वर्किंग कमेटी सदस्य हिस्सा ले रहे थे, जिनमें दो विशेष आमंत्रित भी शामिल थे। बैठक में अपने अध्यक्षीय भाषण में ई बालानंदन ने सोवियत संघ की ताजातरीन घटनाओं के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने, साम्राज्यवादियों द्वारा समर्थित प्रति-क्रांतिकारी ताकतों की गतिविधियों को रेखांकित किया और साम्राज्यवाद के खिलाफ तथा अक्टूबर क्रांति की भावना के अनुरूप समाजवाद की हिफाजत के लिए, तीव्रतर संघर्ष का आह्वान किया।

देश के सूरते-हाल का जिक्र करते हुए सीटू अध्यक्ष ने भारत को नव उपनिवेशवादी जाल में फंसाने की साम्राज्यवादियों के प्रभुत्व में आइ एम एफ द्वारा रची जा रही साजिशों के बारे में आगाह किया और आइ एम एफ द्वारा थोपी जा रही नीतियों को रद्द कराने के लिए मजदूर वर्ग की एकजुट सीधी कार्रवाई का आह्वान किया।

महासचिव की रिपोर्ट

एम के पंधे ने महासचिव के नाते अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हालात की संक्षिप्त रूपरेखा पेश करते हुए, उसे राष्ट्रीय परिस्थितियों के साथ जोड़ा गया और विस्तार से बताया गया कि किस प्रकार इंका की नरसिंह राव सरकार ने आइ एम एफ के नुस्खे के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं। आइ एम एफ ऋण से शुरू कर, महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में अवमूल्यन के खतरनाक नतीजों, व्यापार व उद्योग नीति तथा संघीय बजट, आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस सबसे न सिर्फ आम आदमी पर असह्य बोझ पड़ेगा, बल्कि जनता के सभी तबकों को साम्राज्यवाद द्वारा शोषण के नये से नये रूपों का भी सामना करना पड़ेगा और देश की आर्थिक राष्ट्रीय संप्रभुता खतरे में पड़ जायगी।

शर्तों के साथ आइ एम एफ का ऋण स्वीकार कर सरकार ने देश को कर्ज के फंदे के और नजदीक धकेल दिया है। अवमूल्यन से व्यापार असंतुलन और बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा के संचित कोष पर दबाव और बढ़ जायगा। लाइसेंसिंग खत्म करने, नियंत्रण खत्म करने, नियमन खत्म करने, 51 फीसद विदेशी हिस्सा पूंजी, एम आर टी पी कानून को खत्म करने, आदि खतरनाक पगों के जरिए आइ एम एफ की शर्तें पूरी करने वाली औद्योगिक नीति, बहुराष्ट्रीय निगमों को आकर भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर अपना शिकजा कसने के लिए न्यौता देने की नीति के सिवा और कुछ नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम किए जाने पर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में उच्च प्रौद्योगिकी के नाम पर निजी क्षेत्र तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के बेरोक-टोक प्रवेश की छूट दिये जाने से, एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण के सारे प्रयासों को भारी धक्का लगा है। यहां तक कि लघु तथा अति लघु उद्योग क्षेत्रों को बड़े व्यापारियों, भारतीय तथा विदेशी, दोनों ही द्वारा अतिक्रमण के लिए खोल दिया गया है। रेल किरायों व भाड़ों में बढ़ोतरी, अप्रत्यक्ष करों में बढ़ोतरी करने वाले केंद्रीय बजट, घाटे की वित्त व्यवस्था, सब्सीडियों में कटौती, उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी आदि के जरिए वास्तव में, आम जनता को निचोड़ने के आइ एम एफ के नुस्खे को ही पूर्णता तक पहुंचाया गया है।

रिपोर्ट में, अन्य केंद्रीय संगठनों तथा फैडरेशनों की राय बनाने लिए सीटू के प्रयासों का जिक्र किया गया। ये प्रयास, एक व्यापक आधार वाली बैठक के आयोजन तथा इस बैठक में आयोजन कमेटी के गठन और इस आयोजन समिति द्वारा 16 सितम्बर के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की तथा 17 सितम्बर को राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों की कन्वेंशन के प्रस्तावित आयोजन, में अपने उत्कर्ष पर पहुच रहे हैं। इन कन्वेंशनों द्वारा देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया जायगा। रिपोर्ट में 27 सितम्बर के 'दिल्ली चलो' कार्यक्रम के आह्वान का भी जिक्र किया गया, जिसका आह्वान वामपंथी तथा राष्ट्रीय मोर्चा में शामिल पार्टियों द्वारा किया गया है और सीटू यूनियनों का आह्वान किया गया कि इसमें बड़े पैमाने पर हिस्सा लें।

रिपोर्ट में असंगठित मजदूरों के क्षेत्र, कामगार महिलाओं के क्षेत्र, और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में संघर्षों, का ब्यौरा दिया गया। रिपोर्ट में डाला सीमेंट फैक्टरी के मजदूरों पर पुलिस की गोलीबारी की ओर ध्यान खींचा गया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की हिफाजत करते हुए बहुत से लोग शहीद हुए। रिपोर्ट में आह्वान किया गया कि निजीकरण के सौदे को रद्द कराने के लिए उनके लगातार जारी संघर्ष को अखिल भारतीय समर्थन दिया जाय।

रिपोर्ट में पृथकतावादी व सांप्रदायिक ताकतों द्वारा, जिनका प्रतिनिधित्व खालिस्तानी, जमाते-इस्लामी तथा आर एस एस-भाजपा-विहिप तिकड़ी द्वारा किया जा रहा है उत्पन्न खतरे की ओर ध्यान खींचा और अनवरत सतर्कता तथा राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष का आह्वान किया। रिपोर्ट में एकता सप्ताह के आयोजन, 6 अप्रैल को बी टी आर की बरसी के आयोजन, सीटू स्पेशल फंड के संग्रह, बी टी आर स्मारक के निर्माण के मामले में प्रगति, आदि की भी समीक्षा की गयी। रिपोर्ट में सभी सांगठनिक पहलुओं पर खास तौर पर जोर दिया गया, जिनमें सदस्यता अभियान, जनतांत्रिक काम-काज, ट्रेड यूनियन शिक्षा आदि भी शामिल है, जिन पर सीटू के सातवें सम्मेलन में और कानपुर में संपन्न जनरल काउंसिल में भी विचार किया गया था।

रिपोर्ट के आखिर में पंधे ने आह्वान किया कि हड़ताल की तैयारी के लिये होने जा रही दोनों कन्वेंशनों में हिस्सा लेने के लिये आम मजदूरों को बड़े पैमाने पर लामबंद किया जाय, ताकि अक्टूबर के शुरु में देशव्यापी हड़ताल को संभव बनाया जा सके।

काली घोष ने ई एस आइ योजना और बी बी चेरियन ने, सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीज (प्रोवीडेंट फंड) द्वारा प्रस्तावित कर्मचारी पेंशन योजना, पर अपने नोट पेश किये।

हड़ताल पर विचार

महासचिव की रिपोर्ट पर हुई बहस में यह बात उभरकर सामने आयी कि सरकार द्वारा उठाये आर्थिक पगों से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये हड़ताल के सिवा और कोई चारा ही नहीं रह गया है। बहस में हिस्सा लेते हुए सदस्यों ने बताया कि किस प्रकार विभिन्न उद्योगों में तथा अलग-अलग राज्यों में इन नीतियों के नुकसानदेह परिणाम सामने आने भी शुरु हो गये हैं। उन्होंने मौजूदा नीतियों के परिणामों के तौर पर मिलबंदियों, महगाई, सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न विभागीय कार्यों के निजीकरण, आर्थिक मांगें स्वीकार करने में प्रतिरोध, आदि की ओर ध्यान खींचा। इसके साथ ही बहस में यह भी रेखांकित किया गया कि किस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय हालात का फायदा उठाकर ट्रेड यूनियन आंदोलन को विभाजित करने और वामपंथी ट्रेड यूनियनों को अलग थलग डालने के लिये अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में बी एम एस की भूमिका को खास तौर पर रेखांकित किया गया, जिसने सरकार की नीतियों का समर्थन करने और प्रबंधकों की लाइन की हां में हां मिलाने का ही रास्ता अपनाया है। वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने बताया कि किस प्रकार राज्य, जिला तथा यूनियन स्तरों पर इसके लिये कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं कि अन्य यूनियनों के साथ मिलकर, आम मजदूरों को लामबंद कर संयुक्त जनकार्रवाइयां आयोजित की जाय, जो अखिल भारतीय हड़ताल के आयोजन में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगी। इन कार्रवाइयों के जरिए मौजूदा आर्थिक नीतियों के मजदूर-विरोधी, जनविरोधी तथा राष्ट्रविरोधी चरित्र से आम मेहनतकशों को अवगत कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ वर्किंग कमेटी सदस्यों ने अक्टूबर क्रांति की उपलब्धियों की हिफाजत करने और भारतीय जनता तथा मजदूर वर्ग की साम्राज्यवादविरोधी परंपराओं को आगे बढ़ाने का भी संकल्प व्यक्त किया।

सदस्यों की राय

रिपोर्ट पर बहस की शुरूआत करते हुए बीरेन राय (पं. बंगाल) ने जोर देकर कहा कि समाजवाद के विफल होने का सवाल ही नहीं उठता है। पूंजीवादी व्यवस्था का अनुभव मजदूर वर्ग के संघर्षों को पैदा किये बिना नहीं रह सकता है। फिर भी, इसके लिये मजदूर वर्ग को समुचित रूप से शिक्षित करने और अभियान चलाने की जरूरत है। सरकार की आर्थिक नीतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने आइ एम एफ ऋण तथा सरकार के अन्य पगों के खिलाफ तथा वैकल्पिक नीतियों के हक में एक गंभीर अभियान चलाने और इस अभियान को हड़ताल की तैयारी का हिस्सा बना देने का आह्वान किया।

प. बंगाल से ही काली घोष ने नई औद्योगिक नीति से बढ़ने वाली असमानताओं से क्षेत्रवाद के भड़कने के खतरे की ओर ध्यान खींचा। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि सरकार की घोषणाओं के मुताबिक इकाइयों को बी आई एम आर के हवाले किया जायगा इसका मतलब यह है कि इन इकाइयों को खत्म कर दिया जायगा और मजदूरों को कोई मुआवजा तक नहीं मिलेगा। इसके अलावा, इस नीति के चलते छोटी इकाइयां बंद होती जा रही होंगी। इस प्रकार प. बंगाल, जो लघु औद्योगिक इकाइयों के मामले में देश में सबसे आगे है, बुरी तरह इनकी

मार का शिकार होगा। उन्होंने कलकत्ता में आयोजित ट्रेड यूनियन कन्वेंशन का जिक्र किया, जिसमें इंटक ने भी हिस्सा लिया था, और कहा कि प. बंगाल अक्टूबर के शुरू में हड़ताल के आयोजन के लिये पूरी तरह से तैयार है।

प. बंगाल से ही श्यामल चक्रवर्ती ने सोवियत संघ की घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया और बताया कि सोवियत संघ में प्रतिक्रांतिकारी ताकतों द्वारा पश्चिम बंगाल में किस प्रकार की जन-कार्रवाइयां आयोजित की गयी हैं।

एम पद्मलोचनन (केरल) ने केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि केरल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से काजू तथा अन्य नकद फसलों पर ही आधारित है और सरकार की नई आर्थिक नीतियां उसकी इस अर्थव्यवस्था को तबाह कर देने वाली हैं। उन्होंने संक्षेप में बताया कि एक दिन की हड़ताल की तैयारी के लिये राज्य भर में कन्वेंशनों, प्रदर्शनों, शिक्षित करने के अभियानों तथा सेमिनारों आदि के रूप में, किस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है। आर्थिक नीतियों पर सीटू द्वारा एम के पंधे रचित जो पेंफलेट प्रकाशित किया गया है, उसे मलयालम में अनुदित किया जा चुका है और हजारों की तादाद में मजदूरों के बीच बांटा जा चुका है।

ए के पद्मनाभन (तमिलनाडु) ने बताया कि हिंदुस्तान पैट्रोलियम, सलेम स्टील प्लांट, आदि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर इन्हीं नीतियों के चलते असगठित क्षेत्र में हथकरघा, पावरलूम तथा होजरी इकाइयां और गहरे संकट में धंस गई हैं। धागे की कीमतें और ऊपर चली गयी हैं। निर्यात के चलते कपास जो उपलब्ध नही है। मालिकान ने इकाइयां बंद करना शुरू कर दी हैं। पद्मनाभन ने हड़ताल की तैयारी के लिये राज्य में अपनाये गये कार्रवाई के संयुक्त कार्यक्रम के भी बारे में बताया। उनका कहना था कि इस अभियान में सीटू द्वारा प्रकाशित सामग्री का पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि मौजूदा आर्थिक नीतियों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, दोनों पर ही और ज्यादा शिक्षाप्रद पेंफलेटों तथा लेखों का प्रकाशन किया जाना चाहिए।

चंद्रशेखर (पंजाब) ने बताया कि नई औद्योगिक नीति के बाद से पंजाब में लगभग आधी लघु औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हड़ताल की तैयारी के लिये एक सयुक्त राज्य स्तरीय कन्वेंशन के आयोजन का फैसला भी लिया जा चुका है। अक्टूबर में एक दिन की हड़ताल के आयोजन के लिए जोर-शोर से तैयारी भी शुरू हो चुकी है।

अमलघोष दस्तीदार (असम), डी जी नरसिम्हराव (आंध्र प्रदेश), जे एस मजूमदार (बिहार) एस एन सोलकी (हरियाणा) हेतराम बेनीवाल (राजस्थान), एस कुमार (मध्य प्रदेश), वी जे के नायर (कर्नाटक), हरसहाय सिंह (उ. प्र.), एस बी भारद्वाज (दिल्ली), सुबोध मेहता (गुजरात), शिवाजी पटनायक (उड़ीसा) तथा अन्य वर्किंग कमेटी सदस्यों ने हड़ताल के लिये अपने-अपने राज्यों में की जा रही तैयारियों के बारे में बताया। कुछ अन्य ट्रेड यूनियनों द्वारा पैदा की जा रही समस्याओं के बावजूद सभी राज्यों में अक्टूबर के शुरू में हड़ताल के आयोजन के लिये जोर-शोर से तैयारियां चल रही होने की जानकारी सदस्यों ने दी।

डाला : निजीकरण के खिलाफ संघर्ष

निजीकरण के मुद्दे पर चर्चा करते हुए वर्किंग कमेटी सदस्यों ने डाला सीमेंट फैक्टरी में मजदूरों पर गोलीबारी और डाला के बहादुर मजदूरों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए विभिन्न राज्यों में तथा औद्योगिक केंद्रों में आयोजित कार्रवाइयों का जिक्र किया।

पी के गांगुली ने निजीकरण के खिलाफ डाला सीमेंट मजदूरों की कठिन लड़ाई पर एक प्रस्ताव पेश किया और बताया कि किस प्रकार यह लड़ाई डाला में ही नहीं, लखनऊ में भी चलायी गई, जहां एक मजदूर की पुलिस कार्रवाई में मौत हो गयी। यह संघर्ष एकता समिति के झंडे तले चलाया जा रहा है, जिसमें सभी ट्रेड यूनियनें तथा अफसरान की एसोसिएशनें शामिल हैं। सुनील बसुराय ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, शिवाजी पटनायक तथा हराधन राय के साथ अपने लखनऊ दौरे के बारे में बताया।

सदस्यों ने ई एस आइ तथा पेंशन योजना पर रिपोर्टों पर विचार किया और विभिन्न असंगतियों की ओर ध्यान खींचा। बैठक ने सेक्रेटेरियट को इसके लिये अधिकृत किया कि इन मुद्दों पर सीटू का ठोस रुख तैयार करे तथा सीटू की ओर से सुझावों को सूत्रबद्ध करे।

बैठक ने पंजाब पर भी एक प्रस्ताव स्वीकार किया। प्रस्ताव, बलवंत सिंह ने पेश किया और के रमणि ने प्रस्ताव का समर्थन किया। एक अन्य प्रस्ताव बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में पेश किया गया। त्रिपुरा में अर्द्ध-फासी निजाम की भर्त्सना करते हुए और वहां के मजदूरों के बहादुरीपूर्ण संघर्ष की सराहना करते हुए भी एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यह प्रस्ताव वी बी चेरियन ने पेश किया और पी के गांगुली ने उसका समर्थन किया।

मुख्य प्रस्ताव

बहस के बाद सरकार की आर्थिक नीतियों पर बैठक का मुख्य प्रस्ताव आर उमानाथ ने पेश किया और मनोरंजन राय ने उसका अनुमोदन किया। के एन रवींद्रनाथ, पी के गांगुली तथा रमणिका गुप्त भी प्रस्ताव पर बोलीं।

एम के पंधे द्वारा बहस के दौरान उठे सवालों का जवाब दिये जाने के बाद, रिपोर्ट सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी। ई बालानंदन के समापन भाषण के साथ बैठक का समापन हुआ। उन्होंने, सभी यूनियनों का जोरदार आह्वान किया कि देशव्यापी हड़ताल के लिये एक एक मजदूर तथा एक-एक ट्रेड यूनियन को लामबंद करें और इस काम में पूरी सांगठनिक ताकत को लगा दें।

बैठक ने यह भी तय पाया कि 7 नवंबर से 17 नवंबर तक की अवधि का, अक्टूबर क्रांति की रक्षा के दिनों के रूप में पालन किया जायगा और इस सिलसिले में जल्द ही एक पॅफेलेट प्रकाशित किया जायगा।

केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सीटू वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव

दिल्ली में 1 से 3 सितंबर तक हो रही सीटू वर्किंग कमेटी की यह बैठक कांग्रेस (आइ) की अल्पमत सरकार की ऐसी दूरगामी तथा अभूतपूर्व आर्थिक नीतियां अपनाने के लिए भर्त्सना करती है, जिन्हें अपनाया जाना हमारे देश की संप्रभुता को आइ एम एफ तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथों बेचे जाने के सिवा और कुछ नहीं है।

यह बैठक, सरकार की इस दलील को ठुकराती है कि भुगतान संतुलन की मौजूदा समस्या को हल करने के लिए आइ एम एफ के ऋण के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। यह संकट खुद कांग्रेस (आइ) का पैदा किया हुआ है। यह दलील 1981 में भी इंदिरा गांधी की सरकार ने उस समय दी थी जब विस्तारित ऋण सुविधा के तहत आइ एम एफ से ऐसा ही ऋण लिया गया था। उक्त ऋण खुद कड़ी शर्तें लगाकर दिया गया था। इसके बाद राजीव सरकार ने इसी राह पर देश को आगे बढ़ाया और इसीने देश को मौजूदा संकटपूर्ण हालत में पहुंचाया है जहां भुगतान संतुलन संकट बहुत बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऋण लेकर किये जा रहे अंधाधुंध आयातों से ऋण संबंधी भुगतानों का अनुपात आयात आय के लगभग 30 फीसद हिस्से के बराबर तक पहुंचा दिया है जबकि अस्सी के दशक में यही हिस्सा दस से बारह फीसद ही हुआ करता था। जाहिर है कि इससे विदेशी मुद्रा के सुरक्षित कोष से बाहर की ओर प्रवाह बढ़ता गया है। इसके ऊपर से बिल्कुल अफरा-तफरी का आलम पैदा करने के लिए ताकि डर से लोग मुद्राकोष के सामने घुटने टेके जाने को अपरिहार्यता के रूप में स्वीकार कर लें, भारत के सुरक्षित स्वर्ण कोष में से सोना बैंक आफ इंग्लैंड के पास रेहन रखाने के लिए वहां तक पहुंचाया गया है। ऋण लेकर सरकार ने हमारे देश को, लैटिन अमरीकी देशों के जैसे ही ऋण के फंदे के और भी नजदीक पहुंचा दिया है।

रुपये का बीस फीसद अवमूल्यन, व्यापार नीतियों में बदलाव और रेल तथा आम बजट आदि दूसरे सभी पग, ऋण की शर्तों के अपरिहार्य तथा अनिवार्य अंगों तथा उपांगों के रूप में सामने आये हैं।

यह दलील कि रुपये के अवमूल्यन तथा व्यापार नीति में परिवर्तनों से निर्यात बढ़ेंगे तथा आयात घटेंगे तथ्यों की तुला पर सही नहीं बैठती हैं। अनुभव यही दिखाता है कि भारत तथा तीसरी दुनिया के अन्य देशों के निर्यातों पर, इसके पहले अवमूल्यनों का कोई खास असर नहीं पड़ा था। उल्टे इन देशों का व्यापार संतुलन ज्यादा से ज्यादा ऋणात्मक ही होता गया है। रुपये के बीस फीसद अवमूल्यन से आयात बिल बढ़ जायगा तथा व्यापार असंतुलन और बढ़ेगा और इस प्रकार विदेशी मुद्रा संचित कोष पर दबाव और बढ़ता जायगा। पुनः इसमे अपने आप आयातित मालों की कीमतें बढ़ जायंगी और इससे कड़ी दर दूसरे सभी मालों की भी कीमतें बढ़ जायंगी और मुद्रास्फीति का वक्र ऊपर ही चढ़ता जायगा। इससे, मजदूरों की वास्तविक मजदूरी घटेगी और घरेलू बाजार और सिकुड़ेगा, मंदी होगी, मिलबंदियां बढ़ेंगी और बेरोजगारी बढ़ेगी, इस प्रकार आइ एम एफ तथा अवमूल्यन ही देश को एक दुश्चक्र में धकेल देगा और आम आदमी को साम्राज्यवादी देशों के नव-उपनिवेशवादी निर्मम शोषण का सामना करना पड़ेगा।

सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति से आत्मनिर्भरता के पूरी तरह से खत्म हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। बुनियादी (कोर) क्षेत्र के दायरे में जो 1956 के औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव में सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रक्षित था भारतीय तथा विदेशी भी, निजी क्षेत्र के प्रवेश की इजाजत देकर सरकार ने उनके लिए, खासतौर पर बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए द्वार चौपट खोल दिये हैं कि वे आय और भारतीय अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कायम कर लें। लाइसेंसिंग खत्म करने, नियमन खत्म करने, नियंत्रण खत्म करने तथा 51 फीसद विदेशी ईक्विटी हिस्सेदारी के जरिए फेरा को निष्प्रभावी बनाने और परिसंपत्तियों की सीमा हटाने के जरिये एम आर टी पी को लगभग खत्म ही करने के जरिए, सरकार ने नियोजित राष्ट्रीय आर्थिक विकास से दामन ही छुड़ा लिया है। सरकार ने बैंकिंग तथा सेवाओं का क्षेत्र बहुराष्ट्रीय निगमों को सौंपने के लिए कदम उठाने शुरू किये हैं ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनका पूरा नियंत्रण हो सके। इसी प्रक्रिया में भारतीय पेटेंट कानून तथा बौद्धिक संपत्ति अधिकारों को भी बदला जायगा। ऐसे में अमरीकी साम्राज्यवादियों को भारत के सिर पर सुपर-301 तथा स्पेशल-301 की तलवार लटकाये रखने की जरूरत क्यों रह जायगी!

और जैसे इतना ही काफी न हो, इजारेदारों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों को लघु उद्योगों के क्षेत्र में भी घुसने की इजाजत दी जा रही है। कृषि-औद्योगिक क्षेत्र को विदेशी पूंजी के लिए खोला जाना, उसे किसानों को निचोड़ने की इजाजत देगा जो पहले ही कांग्रेस के लंबे शासन में सबसे ज्यादा शोषित रह हैं।

नयी औद्योगिक नीति से मिलबंदियों तथा उद्योगों के बीमार होने की प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। उसमें बड़ी नंगई से यह एलान किया गया है बीमार इकाइयों को बी आइ एम आर के हवाले किया जा सके। यह नीति घरेलू प्रौद्योगिकी, परंपरागत तथा छोटे उद्योगों को नष्ट कर देगी और देश में बेकारी की समस्या को और उग्र बना देगी।

उपरोक्त आर्थिक पगों तथा रेल किरायों व भाड़ों में बढ़ोतरी की पृष्ठभूमि में आये केंद्रीय बजट ने मेहनतकश जनता के सभी तबकों पर और ज्यादा बोझ डाले हैं। उर्वरकों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की मार आम जनता पर पड़ेगी। आइ एम एफ की शर्तों के चलते सब्सीडियों में कटौती ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर दबाव बहुत बढ़ा दिया है। यह निंदनीय है कि सरकार ने अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए न

तो प्रत्यक्ष कर या सम्पत्ति कर बढ़ोतरी की है और न काले धन की विशाल राशि से ही वसूली करने का कोई प्रयास किया है।

आइ एम एफ द्वारा थोपे गये चौतरफा आर्थिक पग, मजदूर वर्ग तथा आम जनता पर एक चौतरफा हमला है। इसका सरकार की श्रम नीति पर भी असर होगा और इसके चलते मजदूर वर्ग तथा उसके ट्रेड यूनियन अधिकारों पर एक नया हमला छेड़ा जायगा। इन नीतियों से, देश की आर्थिक संप्रभुता के लिए खतरा नहीं पैदा हो गया है बल्कि देश की स्वतंत्रता व स्वाधीनता के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।

यह बैठक, पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार द्वारा रखे गये वैकल्पिक सुझावों का और आर्थिक संप्रभुता की हिफाजत करने के लिए जुलाई में दिल्ली में वामपंथ के तत्वावधान में आयोजित अर्थशास्त्रियों की कन्वेंशन द्वारा स्वीकृत वक्तव्य का स्वागत करती है और इन सुझावों को स्वीकार न करने के लिए केन्द्र सरकार की भर्त्सना करती है, वर्किंग कमेटी, सभी सबद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि इन विकल्पों को आम मजदूरों के बीच ले जाय।

वर्किंग कमेटी, भारत की नयी आर्थिक नीति के खिलाफ प. बंगाल में बनी ट्रेड यूनियनों की लगभग मुकम्मल एकता का अभिनंदन करती है और एक दिन की विरोध हड़ताल के आयोजन के उनके संयुक्त अनुरोध पर अनुकूल रुख के साथ गौर करती है।

वर्किंग कमेटी, समूचे मजदूर वर्ग तथा सभी ट्रेड यूनियनों का आह्वान करती है कि अपनी राजनीतिक संबद्धताओं से ऊपर उठकर एकजुट होकर वक्त की चुनौती स्वीकार करें और नये आर्थिक कदमों को रद्द किये जाने की मांग करते हुए जबर्दस्त विरोध कार्रवाइयों और देशव्यापी हड़ताल का आयोजन करें। कमेटी, जनता के सभी देशभक्त जनतांत्रिक हलकों से अपील करती है कि देश के हित में इस आंदोलन को अपना समर्थन दें। वह जनता के सभी तबकों से, जिन पर सरकार की नयी आर्थिक नीतियों का प्रतिकूल असर पड़ने जा रहा है अपील करती है कि इस आंदोलन में शामिल हों तथा उसे मजबूत बनायें।

बैठक अनेक केंद्रीय ट्रेड यूनियनों तथा फेडरेशनों द्वारा संयुक्त रूप से दिल्ली में 16 तथा 17 सितंबर को क्रमश: सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की ओर से सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ, कन्वेंशनें आयोजित किये जाने के फैसले का स्वागत करती है। इन कन्वेंशनों में आर्थिक पगों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक दिन की हड़ताल की तारीख तय की जायगी।

बैठक बैंकिंग उद्योग के कर्मचारियों तथा अफसरान को बधाइयां देती है जिन्होंने बैंकों के निजीकरण की कोशिशों के खिलाफ 6 सितंबर को हड़ताल आयोजित करने का फैसला लिया है। बैठक सीटू यूनियनों का आह्वान करती है कि अन्य यूनियनों के साथ मिलकर यह दिन, निजीकरण की नीति के विरोध दिवस के रूप में मनाए।

वर्किंग कमेटी किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करती है जो उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में लड़ाई के मैदान में आयी है।

बैठक, इन्हीं आर्थिक पगों का विरोध करने के लिए 27 सितंबर को दिल्ली में बोट क्लब पर लाखों मजदूरों, किसानों तथा अन्य तबकों की देशव्यापी रैली आयोजित करने के लिए वामपंथ तथा राष्ट्रीय मोर्चा में शामिल पार्टियों के फैसले का स्वागत करती है। वर्किंग कमेटी, मजदूरों के सभी हिस्सों से अपील करती है कि इस विशाल रैली में भारी से भारी संख्या में हिस्सा लें।

बैठक, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, दोनों के मजदूरों तथा केंद्र व राज्य सरकार कर्मचारियों से अपील करती है कि इस जोरदार हड़ताल में शामिल हों और एकजुट होकर जुझारू कार्रवाइयों के लिए आगे बढ़ें ताकि राष्ट्रीय संप्रभुता का झंडा बुलंद रखा जा सके और सरकार को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर किया जा सके।

वाम–राष्ट्रीय मोर्चा की विशाल रैली

27 सितंबर 1991 को नई दिल्ली में बोट क्लब पर वाम-राष्ट्रीय मोर्चा द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें दस लाख लोगों से भी अधिक ने भाग लिया। रैली नरसिंहा राव की कांग्रेस (आई) सरकार द्वारा अपनायी जा रही नई आर्थिक और औद्योगिक नीतियों के विरोध में आयोजित की गयी। मजदूर, किसान, विद्यार्थी, नौजवान तथा महिलाएं देश के सभी राज्यों से रैली में शामिल होने के लिए आये। विशाल जुलूस लाल किले से आरम्भ होकर बोट क्लब पर विशाल सभा में परिवर्तित हो गया। रैली में आये लोगों ने वामपंथी पार्टियों के लाल झंडे और बैनर तथा जनता दल के हरे झंडे हाथों में उठा रखे थे।

रैली को संबोधित करने वालों में सी पी आई(एम) के हरकिशन सिंह सुरजीत व सैफुद्दीन चौधरी, सी पी आई के चतुरानन मिश्रा व इंद्रजीत गुप्ता, आर एस पी के नानी भट्टाचार्य, फारवर्ड ब्लाक के चित्त बसु, टी डी पी के एन टी रामा राव, कांग्रेस (एस) की श्रीमति मुस्तफा तथा जनता दल के वी पी सिंह, राम विलास पासवान, लालू यादव, शरद यादव और मुफ्ती मोहम्मद सयीद शामिल थे। रैली ने एक ग्यारह सूत्री प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जिसमें मूल्य वृद्धि, तालाबंदी निजीकरण, आइ एम एफ लोन, के विरुद्ध और मजदूरों की प्रबंध में भागीदारी, भूमि सुधार, किसानों के लिए उपज के लाभकारी मूल्य तथा दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ कदम उठाने की मांग की गयी थी।

रैली ने एक अन्य प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया। यह प्रस्ताव 29 नवंबर को देशव्यापी औद्योगिक हड़ताल को पूर्ण समर्थन देता है। इस हड़ताल का सरकार को अपनी नीतियां बदलने के लिए बाध्य करने के लिए ट्रेड यूनियनों द्वारा आह्वान किया गया है (रैली की विस्तृत रिपोर्ट अगले अंक में छापी जाएगी)।

अध्यक्षीय भाषण

ई० बालानंदन

प्रिय कॉमरेड,

मैं आप सबकी ओर से इल्ला सीमेंट फैक्ट्री (उ० प्र०) के मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हू, जो निजीकरण-विरोधी अपने संघर्ष में पुलिस की गोलियों के शिकार हुए। पंजाब में कई और बेगुनाह लोग आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हुए। मैं आपकी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। त्रिपुरा में कांग्रेस ई—टी. यू. जे. एस. सरकार द्वारा फैलाया गया अर्द्ध-फासीवादी आतंक जारी है। प्रशासन व पुलिस की सहायता से, पुलिस व किराये के गुण्डों ने पिछले आम चुनावों के दौरान अनेक वाम मोर्चा समर्थकों को मार दिया। मैं आप सबकी ओर से उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं मजदूर वर्ग के नेताओं, कार्यकर्ताओं व लोकतांत्रिक आन्दोलन से जुड़े उन सभी साथियों की स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करता हू, जिनका इस अवधि में निधन हो गया।

दूसरे मुद्दों पर आने से पहले मैं अपने उपाध्यक्ष कॉ० ज्योति बसु व वाम मोर्चा को पिछले आम चुनावों में शानदार विजय के लिए बधाई देता हू। पश्चिम बंगाल की जनता ने चौथी बार वाम मोर्चे में अपना विश्वास व्यक्त किया है, जो कि अपने आप में एक बेमिसाल बात है। हमें इस बात पर बेहद प्रसन्नता है कि पश्चिम बंगाल के मजदूर संगठनों ने वाम मोर्चे का साथ देकर उसकी विजय सुनिश्चित की। पश्चिम बंगाल सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत, अनेक दबावों के रहते जनता की सेवा की। इससे उसने जनता की शुभाकांक्षाएं अर्जित की हैं। पश्चिम बंगाल एक बार पुनः देश की अग्रणी लोकतांत्रिक राज्य के रूप में उभरकर आया है।

13-17 फरवरी, 1991 को कलकत्ता में हुए अपने सातवें सम्मेलन में हमने तात्कालिक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विचार किया था। इस अवधि में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर अनेक परेशानी उत्पन्न करने वाली घटनाएं हुई। सातवें सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में कॉ. ज्योति बसु ने अन्य बातों के अतिरिक्त खाड़ी युद्ध को लक्ष्य करके कहा था—"इस युद्ध में वास्तविक मुद्दा पश्चिम एशिया के 'तेल-प्रमुख' इलाकों पर प्रभुत्व का बन गया है। आखिर सउदी अरब, ईराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत व ईरान में कुल तेल उत्पादन का 65 प्रतिशत होता है।" अमरीका ने अपने साम्राज्यवादी साथियों तथा कुछ अरब सरकारों के साथ मिलकर ईराकी प्रतिरोध को कुचल दिया।

जहां विश्व की लोकतांत्रिक शक्तियों द्वारा कुवैत की आजादी की मांग की गयी थी, वहां अमरीका व अन्य साम्राज्यवादी देशों का असली मकसद सिर्फ ईराकी को कुवैत से बाहर करना नहीं था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अनेक प्रस्तावों की आड़ में ईराक का दमन जारी रखा। वे मध्य-पूर्व में अपनी सैनिक उपस्थिति बढ़ाते गये ताकि विश्व के तेल क्षेत्रों पर उनका कब्जा हो सके। हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि मध्य पूर्व में पूंजीवादी ताकतों की उपस्थिति—चूंकि मध्य-पूर्व यूरोप, एशिया और अफ्रीका का मिलान बिन्दु है—इन महाद्वीपों के निवासियों के लिए खतरनाक है।

यह सैनिक जमावड़ा इनके उन सैनिक अड्डों के अतिरिक्त है जो पहले विश्वभर में एक जाल की तरह फैले हुए हैं जैसे—दिएगो गार्सिया, क्लर्क फील्ड तथा क्यूबिक की खाड़ी आदि।

यहां एक बात पर विशेष बल देने की आवश्यकता है और वह है खाड़ी युद्ध में सोवियत संघ की भूमिका। दरअसल इस मसले पर सोवियत संघ ने अमरीका की नीतियों का अनुसरण किया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीन ने भी अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया तथा अमरीकी चालबाजियों से अपने को दूर करने का ठोस प्रयास नहीं किया।

खाड़ी युद्ध में विजय के बाद अमरीका अब फिलिस्तीनी जनता के एकमात्र प्रतिनिधि संगठन, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। खाड़ी युद्ध का विशेष शिकार अरब-एकता बनी है। अरब राज्यों की संस्था 'ओएस' तथा 'अरब लीग' अरब राष्ट्रों को, सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध लामबंद करने में सफल नहीं हो सकी। प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरब देशों में फूट का लाभ उठाते हुए, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, को दरकिनार करने के लिए ही है। यह फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को और कमजोर करके अरब देशों में विरोध बढ़ाना है। इससे इजराइल की स्थिति और मजबूत व दृढ़ होगी।

कमजोर पड़ता गुट निरपेक्ष आन्दोलन

सोवियत संघ के बदले रवैये के परिणामस्वरूप आज गुट निरपेक्ष आन्दोलन पहले से कमजोर हो चुका है। तृतीय विश्व के देशों की एकता भी कमजोर पड़ चुकी है। मोजाम्बिक, अंगोला व कई अन्य अफ्रीकी देशों में अप-क्रांतिकारी शक्तियां सक्रिय हैं। इथियोपिया में अप-क्रांतिकारी शक्तियों की सफलता तथा अल्जीरिया आदि में रूढ़िवादी शक्तियों के विकास से क्रांतिकारी व राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों को धक्का पहुंचा है।

बर्मी सैनिक गुट ने जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सत्ता सौंपने से इन्कार कर दिया व वहां पर जनता का प्रतिरोध बरकरार है। पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो की चुनी हुई सरकार को पलट दिया गया व इसके स्थान पर सेना की मदद से एक झूठे

चुनाव के जरिये आई. जे. आई. के अतर्गत एक नयी सरकार गठित की गई। श्रीलंका में जारी जातीय सघर्ष से स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है। एल. टी. टी. ई. व सिंहलियों के प्रति श्रीलंका सरकार की नीतियों से समस्या और गंभीर हुई है। भारत-श्रीलंका समझौते को आधार बनाकर, श्रीलंका की एकता व अखंडता के अतर्गत समस्या का समाधान ढूंढ़ना होगा।

लेकिन इन सब आघातों के बावजूद इस अवधि में हुई प्रगति भी उल्लेखनीय है। नामीबिया की आजादी, पश्चिमी सहारा के लिए समझौता, अफ्रीकी नैशनल कांग्रेस की प्रगति, कंपूचिया की बात-चीत में प्रगति, नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का दूसरी शक्ति के रूप में उभरना, बगलादेश में लोकतत्र व ससदीय व्यवस्था की पुनर्स्थापना व भारत-चीन सबधो में आया सुधार प्रगति के लक्षण हैं।

सातवें सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने पूर्वी यूरोप के देशों में आ रहे परिवर्तनों व पूंजीवाद के लिए उनकी आकुलाहट को लक्ष्य करके कहा था—"अनुभव इन लोगों को यह सिखला देगा कि यह रास्ता खुशहाली नहीं ला सकता, हालांकि कई पश्चिमी देश उनका समर्थन कर रहे हैं।" (अध्यक्षीय भाषण, पृष्ठ-4)। आज हम जानते हैं कि इन देशों में सक्रिय शक्ति का 40%-50% बेरोजगार हैं। इन देशों में बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की जानी बाकी है, और वे लोग बड़ी गंभीर स्थिति में हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। यह उनके लिए एक नया अनुभव है। उन्होंने समाजवाद के अतर्गत, निश्चित रोजगार, मुफ्त चिकित्सकीय सेवा, मुफ्त शिक्षा व सस्ती खाद्य सामग्री का अनुभव किया है। जो लोग पूंजीवाद के लिए शोर मचा रहे थे उन्होंने अपने अनुभव से पूंजीवाद और समाजवाद के अन्तर को समझ लिया है तथा वे अपने पुरानों अधिकारों के लिए संघर्ष करने को सगठित हो रहे हैं।

सोवियत संघ का घटनाक्रम

अपने सातवें सम्मेलन में हमने सोवियत सघ की चिन्ताजनक घटनाओ पर विचार किया था व इस बात का भी उल्लेख किया था कि सोवियत सघ में दो प्रकार की शक्तियां सक्रिय हैं—एक वह वर्ग जो समाजवाद का पूरी तरह खात्मा चाहता है तथा दूसरा वर्ग वह जो समाजवादी ढांचे में ही कुछ आर्थिक सुधार चाहता है। हमने कहा था कि हम केवल चिन्तातुर रहकर वहां की घटनाओं पर नजर रख सकते हैं। हमने इस बात का भी उल्लेख किया था कि अमरीका की प्रतिद्वंद्विता में एक महाशक्ति के रूप में रूस की स्थिति कमजोर हो रही है। पिछले छह माह में सोवियत सघ मे स्थिति बद से बदतर हुई है। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री गोर्बाचेव ने यह चालबाजी भरा वक्तव्य दिया कि वे—मार्क्सवाद-लेनिनवाद का परित्याग कर रहे हैं। मजदूर वर्ग की विचारधारा को छोड़ रहे हैं। तथा कम्युनिस्ट पार्टी को समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी में बदल रहे हैं। दरअसल यह प्रयास सोवियत सघ में बुर्जुआ विचारधारा के सामने पूरी तरह समर्पण करके पूंजीवाद को बढ़ावा देने का है। इस बीच 19 अगस्त को तड़के यह खबर आयी कि एक आपातकालीन समिति ने सोवियत सघ में प्रशासन का कामकाज संभाल लिया है। यह फैसला; जैसा कि येल्तसिन ने स्वीकार किया; पूरी कैबिनेट ने लिया था, जिसमें सर्वोच्च सोवियत के चेयरमैन भी शामिल थे। प्रगतिशील लोगों ने यह उम्मीद की थी कि उससे सोवियत सघ व समाजवाद को मजबूत करने व पूंजीवाद की ओर उसके पतन को रोकने में सहायता मिलेगी। गोर्बाचेव की अनुपस्थिति में येल्तसिन जॉर्ज बुश के साथ लगातार सपर्क बनाये हुए थे। सत्ता में लौटने के बाद गोर्बाचेव ने घोषणा की कि वे कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे रहे हैं साथ ही यह भी कहा कि वे सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति को भग कर रहे हैं जिसे 27वीं पार्टी कांग्रेस में चुना गया था। रूसी संसद में उन्होंने घोषणा की कि "राजनैतिक ताकतों के पुनर्गठन की आवश्यकता है। हमें एक विश्वसनीत सरकार की आवश्यकता है। उन्होंने येल्तसिन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं कि "यदि हम में से कोई अपने कार्य को सभालने में असफल रहता है तो दूसरे में व्यक्ति स्वयमेव उसके अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।" क्या यह कोई व्यापारिक लेन देन है? गोर्बाचेव और येल्तसिन सोवियत सघ पर शासन करने के अधिकार के हस्तांतरण पर सहमत हो गये हैं। यह हर तरह से हास्यास्पद व्यवस्था है।

अनेक गणराज्यों में कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों को रोक दिया गया है या उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूरे सोवियत सघ में एक समाजवाद विरोधी लहर चल रही है, जिसका उद्देश्य पूंजीवाद के लिए रास्ता साफ करना तथा समाजवाद के बचाव में होने वाले सघर्ष को कमजोर करना है। अनेक गणराज्यों में कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तरों को सील कर दिया गया है व उनकी गतिविधियों पर रोक लगा दी गयी है। गोर्बाचेव के चुने हुए उत्तराधिकारी येल्तसिन ने रूसी गणतत्र में फैक्ट्रियों व दफ्तरों में पार्टी के काम को रोक दिया है। पूरे सोवियत सघ मे कम्युनिस्ट पार्टी पर हमले हो रहे हैं। गोर्बाचेव जो कानूनी ढंग से काम-काज की बात कर रहे हैं, उन्होंने लुक्यानोव को सर्वोच्च सोवियत के चेयरमैन के पद से, बिना सर्वोच्च सोवियत की सलाह के हटा दिया। पश्चिमी ताकतें इसी प्रकार के लोकतत्र के लिए शोर मचा रही है। 20 अगस्त को जिस तथाकथित सघ समझौते पर दस्तखत होने थे। उसमें निम्नलिखित खतरनाक व्यवस्थाएं थीं—

आर्थिक, विदेश व्यापार, तथा वित्त मामलों में गोर्बाचेव ने संतुलन गणराज्यों की ओर झुकाने का प्रयास किया। कर-व्यवस्था गणराज्यों को सौंप दी गयी है। केन्द्रीय बजट पर गणराज्यों की सहमति आवश्यक है तथा विदेश व्यापार गणराज्यों के लिए छोड़ दिया गया है। यदि 20 अगस्त को इस समझौते पर दस्तखत हो जाते तो इससे सोवियत सघ की शक्ति छिन्न-भिन्न हो जाती तथा राज्यों को केन्द्र से ज्यादा अधिकार दे दिये जाने से सोवियत सघ का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता।

बहरहाल अब कम्युनिस्ट विरोधी लहर से यह प्रक्रिया आसान हो गयी।

बिखराव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। तीन बाल्टिक गणराज्यों ने स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी और उनके बाद यूक्रेन, बाइलोरशिया और मान्दाविया ने भी अपने आप को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। जॉर्जिया तथा अर्मीनिया ने सन्धि को न मानने की पहले ही घोषणा कर दी है।

सोवियत संघ में जातीय संघर्ष भी चरम सीमा पर पहुंच गया है। सोवियत संघ में जारी नीति के अन्तर्गत कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, पार्टी के दफ्तरों और काम-काज पर रोक लगा दी गयी है, प्रतिष्ठित बोल्शेविक नेताओं को नज़रअन्दाज किया जा रहा है, और सब से बढ़कर वहां प्रति-क्रांतिकारी शक्तियों द्वारा 70 साल पुराने इतिहास को दोहराने का प्रयास कि जा रहा है।

1917 में अक्टूबर में महान समाजवादी क्रान्ति ने पूरी मानवजाति का भविष्य बदल दिया था। इससे प्रथम समाजवादी राज्य का जन्म हुआ, प्रथम शोषण विहीन राज्य अस्तित्व में आया, एक तिहाई विश्व को पूंजीवाद तथा अन्य शोषक व्यवस्थाओं से मुक्त कराया और इस प्रकार शोषित तथा दबे कुचले तबके के उद्धार के सपने को पूरा किया। इसने विश्व भर में उत्साह पैदा किया तथा मजदूर व शोषित वर्ग को शोषण के विरुद्ध उठ खड़े होने की प्रेरणा दी। सोवियत संघ के उदय के बाद दो विश्व अस्तित्व में आये—एक समाजवादी और दूसरा पूंजीवादी। सोवियत संघ ने अपने उदय से ही विश्व भर में लोकतंत्र, स्वाधीनता, शान्ति तथा प्रगति के लिए संघर्षरत मानवता के अगुआ की भूमिका निभाई। सोवियत संघ ने विकासशील समाजवाद की सुरक्षा करने में साम्राज्यवाद व तमाम प्रतिक्रियावादी विश्व पर शानदार विजय हासिल करते हुए मजदूरवर्ग तथा विश्व भर के मुक्ति आन्दोलनों को प्रेरणा दी थी।

क्रांति के बाद थोड़े से समय में ही एक कमजोर और पिछड़े राज्य के स्थान पर सोवियत जनता ने कॉ. स्टालिन और सी. पी. एस यू. के नेतृत्व में कॉ लेनिन और बोल्शेविक पार्टी द्वारा रखी नींव पर एक विकसित व शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर दी। थोड़े से समय में ही सोवियत संघ ने जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से उन्नति की और इस प्रकार पूंजीवाद तथा अन्य व्यवस्थाओं पर समाजवाद की श्रेष्ठता साबित की।

सोवियत जनता व सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने कॉ. स्टालिन के नेतृत्व में उस समय की क्रूरतम शक्तियों—नाज़ी जर्मनी व धुरी शक्तियों को परास्त कर, सपूर्ण मानवता की रक्षा की थी तथा इतिहास के दोहराये जाने को रोका था।

शानदार फासिस्ट विरोधी विजय से एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका में अनेक देशों के मुक्ति आन्दोलनों के लिए रास्ता बनाया था तथा इस प्रकार इन देशों में सदियों पुराने उपनिवेशवाद को इतिहास की रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। हालांकि युद्ध ने सोवियत अर्थव्यवस्था पर अत्यंत बुरा प्रभाव डाला था लेकिन उसने थोड़े से समय में तेजी से प्रगति की व अपने आपको किसी भी साम्राज्यवादी हमले का जवाब देने में सक्षम बनाया। सोवियत नेतृत्व ने ही चीनी क्रान्ति के लिए प्रेरणा दी थी, जिसके द्वारा विश्व के सबसे अधिक जनसख्या वाले देश में समाजवाद आया था। इसी सोवियत नेतृत्व ने कोरिया तथा वियतनाम को प्रेरणा दी थी, जिससे वे अमरीका तथा अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों के सैनिक विरोधों का डटकर मुकाबला कर सके तथा उन्हें परास्त करने में सफल हुए। युद्धोपरान्त सोवियत संघ ने ही तीसरे विश्व के अनेक नये स्वतन्त्र हुए देशों की नव-उपनिवेशवादी शोषण से रक्षा की जिसका खतरा उनपर आज भी मंडरा रहा है।

इसने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को प्रतिष्ठा व सम्मान दिलाने में मदद की। तथा एक बार फिर यह समाजवादी राष्ट्र ही था जिसने विश्व शांति के लिए काम करते हुए युद्ध चाहने वाले साम्राज्यवादी खेमे को पराजित करके सम्पूर्ण विश्व की अणु-त्रासदी से रक्षा की।

हालांकि पचास के दशक तक विकास की समस्याओं को सुलझाने में इस एक देश में समाजवादी नेतृत्व से कुछ गलतियां हुईं लेकिन फिर भी विश्व के मजदूर-वर्ग, तथा शान्ति-प्रिय जनता को शोषण तथा युद्ध के विरुद्ध उसके संघर्ष में सोवियत संघ द्वारा प्रदान किया गया नेतृत्व अतुलनीय है। इसके बिना आज विश्व भर में इतनी आज़ादी, प्रगति और शान्ति नहीं हो सकती थी।

अब सोवियत घटना क्रम से न केवल समाजवादी विकास प्रक्रिया को धक्का पहुंचा है बल्कि संपूर्ण मानव जाति का अहित हुआ है क्योंकि यह 70 साल तक विश्व की धारा को प्रगति व शान्ति की ओर मोड़ने की प्रक्रिया को उलटने तथा पुनः पूंजीवाद की ओर जा कर सब कुछ विश्व की एक मात्र महाशक्ति अमरीका के हाथों में सौंपना है। इससे तृतीय विश्व के सभी देशों के लिए समस्या उत्पन्न होगी। इस प्रकार अब पुनः तृतीय विश्व के देशों में साम्राज्यवादी दमन व हस्तक्षेप का अध्याय आरंभ हो गया है।

अपने भीतरघातों की बदौलत साम्राज्यवाद व पूंजीवाद विश्व के अनेक समाजवादी देशों को पुनः पूंजीवादी देशों में बदलने में सफल हो गया है। लेकिन फिर भी यह तथ्य अडिग व किसी भी संदेह से परे है कि विश्व के मज़दूर वर्ग की श्रद्धा वैज्ञानिक विचारधारा में है। तथा समाजवादी विचारधारा का झंडा बुलन्द रखने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। मजदूर वर्ग को उन तबकों का पुनः विश्वास जीतना होगा जो पिछले दो वर्षों के दौरान भ्रमित हो गये हैं।

हालांकि साम्राज्यवादी देश पूंजीवाद के लाभों का राग अलाप रहे हैं लेकिन विश्व का कोई पूंजीवादी देश बहुसख्या समुदाय को बेहतर जीवन नहीं दे सकता। विकसित पूंजीवादी देशों में न केवल पूंजीवाद बढ़ रहा है बल्कि सामाजिक सुरक्षा के लाभों में भी भारी कटौती की जा रही है, जिसे उन्होंने लम्बे संघर्ष के बाद हासिल किया था। अब कल्याणकारी उपायों में

कटौती की रही है तथा कहा जा रहा है कि वे उत्पादन व उत्पादकता के विकास में सहायता नहीं दे रहे हैं। इन देशों में निचले तबके की आय घट रही है तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ रही है। अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने अमरीकी कांग्रेस में लोकतंत्रवादियों के बेरोजगारी भत्तों को चार और सप्ताह तक बढ़ाये जाने के 5.5 बिलियन डॉलर के प्रस्ताव का खुला विरोध किया है। विश्व बैंक की रपट में यह कहा गया है कि पूंजीवादी देशों में आर्थिक संकट अब भी मौजूद है। अतः यह तर्क की पूंजीवाद बेहतर जीवन के लिए विकल्प प्रदान कर सकता है, गलत है। अनुभव से यह बात सही साबित नहीं हुई है जबकि समाजवाद ने अपने आपको सही साबित किया है। अतः सोवियत संघ का पूंजीवाद की ओर वापस जाना विश्व भर के मजदूरवर्ग तथा तीसरी दुनिया के देशों के लिए खतरे की घंटी है। विश्व में अमरीकी साम्राज्यवाद का एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरना एक बेहद गंभीर घटना है।

कॉमरेड,

पूंजीवादी देश समाजवाद के खिलाफ एकमत होते हुए भी, अधिपत्य के लिए आपस में लड़ रहे हैं। जर्मनी के एकीकरण के बाद उसकी आर्थिक शक्ति बढ़ने का खतरा हो गया है, जापान जो कि इलैक्ट्रोनिक उद्योग में पहले ही आगे है, अमरीकी कार बाजार में प्रवेश कर चुका है, जिससे अमरीका प्रतिबंध थोपने पर मजबूर हुआ है। साम्राज्यवाद का अन्दरूनी संघर्ष आने वाले दिनों में अवश्य ही बढ़ेगा।

ऐसे गंभीर समय में यह बात नहीं भुलायी जा सकती कि भारत अपनी ऐसी अनेक उपलब्धियों के लिए जिन पर हम गर्व कर सकते हैं इसी समाजवादी देश—सोवियत संघ—का ऋणी है। जब पाकिस्तान ने शक्तिशाली अमरीकी साम्राज्यवाद की मदद से संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रयास किया था तब सोवियत संघ ने ही उस प्रस्ताव को वीटो किया था तथा सोवियत संघ हमेशा कश्मीर मामले पर दृढ़ रूप से भारत के साथ रहा है।

विकसित पूंजीवादी देश; जिन्होंने आजादी के तुरन्त बाद भारत की सहायता करने से इन्कार कर दिया था; मदद के लिए तभी आगे आये जब सोवियत संघ ने मूलभूत उद्योगों जैसे स्टील, अभियांत्रिकी, तेल व ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की वास्तविक मदद की। यही उद्योग आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विकास का आधार बनते है। बंग्लादेश युद्ध के दौरान अमरीका के सातवें बेड़े के खतरे से भारत की सुरक्षा करने के लिए सोवियत संघ ही आगे आया था, व खतरे को टाला था।

नव उपनिवेशवादी लूट : एक नया हमला

कॉमरेड,

आप जानते हैं कि विश्व के पांच में चार हिस्से आबादी अविकसित देशों में रह रही है। अपने सैकड़ों वर्ष के उपनिवेशवादी अतीत से उपजी पिछड़ेपन की अनेक समस्याओं से उन्हें अभी जूझना है। उन्होंने प्रगति की ओर यात्रा अभी शुरू ही की है। उनके ऊपर 1500 बिलियन डॉलर का कर्ज है, जो उन्हें विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देना है। यह हाल अधिकतर देशों का है, जहां कमायी गयी विदेशी मुद्रा का पचास प्रतिशत कर्ज चुकाने में चला जाता है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित नयी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है कि "संसाधनों का विकसित देशों से अविकसित देशों को स्थानांतरण" जो कि आपसी विश्वास तथा सभी देशों की प्रभुसत्ता के सम्मान की भावना पर आधारित हो। लेकिन अमरीका की मांग जो व्यवस्था थोपने की है वह इन सिद्धांतों के ठीक विपरीत है। उसका इरादा विश्व भर में साम्राज्यवाद का प्रभुत्व स्थापित करने का है। 'बैंक फंड' का इस्तेमाल तीसरी दुनिया के देशों को नव उपनिवेशवादी आधिपत्य की ओर धकेलने के एक प्रमुख अस्त्र के रूप में किया जाता है। विकसित क्षेत्रों के संसाधनों का अविकसित क्षेत्रों में स्थानांतरण करने के विचार का स्थान असमान प्रतियोगिता ने ले लिया है। कॉमरेड, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आपस में गहरा संबंध है। कोई भी देश अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नहीं है तो वह विश्व बैंक से ऋण नहीं ले सकता। विश्व मुद्रा का दर्शन— जिसे विकसित पूंजीवादी देशों ने तैयार किया है तथा जिनमें अमरीका प्रमुख है—ऋण लेने वालों पर अवमूल्यन, मुक्त उद्योग व व्यापार नीतियां, विदेशी निवेश की छूट तथा सब्सिडी समाप्त करने जैसी शर्तें थोपने का है। यह सोच मुद्रा कोष बोर्ड के प्रमुख सदस्य देशों के हितों से गहरा जुड़ा है। मुद्रा कोष निर्णय पद्धति 'कोटा व्यवस्था' पर आधारित है, जो वोट का फैसला करती है। ऋण का फैसला करने के लिए 75 प्रतिशत बहुमत तथा 85 प्रतिशत मतों की आवश्यकता है। 85 प्रतिशत मतों के नियम का लाभ यह है कि इससे अमरीका को वीटो पावर प्राप्त हो जाती है, जिसके पास 19.5 प्रतिशत मत हैं।

कॉमरेड,

अब आप समझ सकते हैं बैंक-कोष के लोगों द्वारा विकसित अविकसित देशों के प्रति अलग-अलग मापदंड क्यों अपनाये जाते हैं। मुद्रा कोष ने अमरीका पर कोई शर्तें नहीं लगायीं तथा भारी घाटा उठाया। आज अमरीका का बजट घाटा विश्व में सबसे अधिक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तीसरी दुनिया के देशों के अपेक्षाकृत कम बजट घाटों के प्रति असहिष्णु है। अब तक का अनुभव यह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के परिणामस्वरूप इन देशों में विकास-प्रक्रिया धीमी पड़ी, विकसित देशों पर निर्भरता बढ़ गयी, राष्ट्रीय वित्त संस्थानों का महत्व घटा तथा सब्सिडी खत्म होते कल्याण योजनाएं बन्द होने तथा वेतन कटौती जैसे कदमों से गरीब वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अपनी नीतियों के शुभ परिणामों की घोषणा के संबंध में मुद्रा कोष की भविष्यवाणियां बिल्कुल गलत साबित हुई हैं। भारतीय संदर्भ में 1981 में लिए गये ऋण के संबंध में कुल घाटे, ब्याज तथा भुगतान संतुलन के संबंध में मुद्रा कोष की

सभी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हैं। ब्राज़ील, चिली, पेरु, बोलिविया, जमेका, फिलिपीन्स, सोमालिया, सूडान, तन्जानिया, लेसोथो तथा घाना के संबंध में असफलता उजागर हुई है, जो पूरी तरह कर्ज जाल में फंस गये हैं। मुद्रा कोष का इरादा तीसरी दुनिया के देशों की वास्तविक समस्याओं का इरादा नहीं है। इसका काम काज इस ढंग से होता है जो विकासशील देशों के लिए नुकसानदेह है। वर्तमान में विश्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विशेषकर अत्यधिक उद्योगीकृत देशों की अर्थव्यवस्था गंभीर तथा जटिल संकट से गुजर रही है। साम्राज्यवादी शक्तियां अपना बोझ तीसरी दुनिया के देशों के लोगों के कंधों पर डालकर अपनी समस्या सुलझाना चाहते हैं व इसके लिए अपने ही मजदूरों तथा जनता की समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। मैं यहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की समस्याओं के विस्तार में जाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। लेकिन तथ्य विश्व बैंक की वर्ष 1991 की रपट में भी स्वीकार किया गया है। रपट में कहा गया है कि "बाहरी प्रभावों के प्रति अत्यधिक खुलाव विकासशील देशों के लिए खतरनाक है। अत्यधिक औद्योगिक देशों का वित्तीय घाटे, कर्ज की ऊंची अंतर्राष्ट्रीय दरों, अमरीका में वित्तीय संस्थानों की खस्ताहालत, जापान की आर्थिक स्थिति का कुछ अंशों में पतन, तथा उरुग्वे में लम्बे समय तक खिंची निर्णयहीन बातचीत का निश्चय ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा।" (पृष्ठ 3 वि. बैंक, 1991)

इस संदर्भ में यह बात समझी जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की शर्तों को मानकर उसका ऋण लेकर कांग्रेसी सरकार ने कितना खतरनाक कदम उठाया है। इन शर्तों के विभिन्न आयामों व उनके परिणामस्वरूप सरकारी नीतियों में बदलाव व सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था पर उसके प्रभाव पर विस्तार से महासचिव की रपट में विचार किया गया है। हमें सभी श्रम संगठनों को लामबन्द करने व संपूर्ण मजदूर व देशभक्त जनता को संगठित करके साम्राज्यवाद द्वारा हमारी आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा विकास को अवरुद्ध करने के प्रयासों को नाकाम करना होगा, क्योंकि अनत: अर्थव्यवस्था ही राजनीति का फैसला करती है। इन नीतियों से जुड़े हमारे स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न देश के रूप में अस्तित्व के लिए खतरे के बारे में विस्तृत प्रचार की आवश्यकता है।

मैं पहले ही समाजवादी व्यवस्था को लगे धक्के के प्रभावों, साम्राज्यवाद के नव उपनिवेशवादी हमले तथा भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियों को स्वीकार कर लिए जाने के खतरों की चर्चा कर चुका हूं।

पंजाब, कश्मीर व असम में फिरकापरस्त चुनौती ज्यों की त्यों मौजूद है। अमरीकी साम्राज्यवाद की शह पर पाकिस्तानी शासक पंजाब व कश्मीर में अलगाववादी ताकतों को खुले आम मदद दे रहे हैं। असम में बढ़ती हुई 'उल्फा' समस्या से खतरनाक स्थिति बन गयी है।

सांप्रदायिक ताकतों के विकास से हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष चरित्र जो कि हमारी एकता का मूल आधार है गंभीर रूप से खतरे में पड़ गया है। वे लोग न केवल सांप्रदायिक आधार पर जनता को विभाजित कर रहे हैं बल्कि मजदूर वर्ग में भी फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक संस्थानों की गंभीर अवमानना करते हुए त्रिपुरा में कांग्रेस—टी. यू जे. एस. सरकार वाम मोर्चा समर्थकों पर हमले जारी रखे हुए हैं। उनके द्वारा फैलाये गये अर्द्ध-फासीवादी आतंक में कमी के कोई आसार नज़र नहीं आते। अत: लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष का विशेष महत्व हो गया है। मजदूर वर्ग की ओर बढ़ते हुए हमलों, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विकास, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु श्रम संगठनों को कमर कस कर अधिकतम एकता स्थापित करनी होगी। इसके अतिरिक्त नयी आर्थिक नीतियों के लागू होने के दुष्प्रभावों से स्थितियां और खराब होंगी। अधिक मिलबंदियाँ, वेतन व भत्तों में अधिक कटौतियां तथा कल्याण योजनाओं में कमी प्रमुख बातें होंगी। मूल्य-वृद्धि आरंभ हो चुकी हैं तथा यह और बढ़कर अगले वर्ष तक दुगनी हो सकती है। सीटू को इस खतरनाक स्थिति से संघर्ष करने के साथके लिए सभी श्रम संगठनों को लामबन्द करना होगा।

सीटू ने मुद्रा कोष पर सरकार द्वारा अपनायी गयी आर्थिक नीतियों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष के लिए श्रम-संगठनों को लामबन्द करने का कार्य आरंभ कर दिया है। 17 सितम्बर को केन्द्रीय श्रम संगठनों की एक कन्वेंशन हो रही है जिसमें एकता आगे के कार्यक्रम पर विचार किया जायेगा।

सीटू देश के सामने उत्पन्न खतरे के विरुद्ध संघर्ष में आगे आने वाले सभी प्रगतिशील तबकों के साथ चलेगी। अत: हमने वामपंथी पार्टियों के साथ मिलकर 27 सितम्बर को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन में शामिल होने का निर्णय किया है।

कामरेड,

मजदूर वर्ग को देश की एकता व संप्रभुता पर आये खतरों से संघर्ष करने वालों में अग्रिम पंक्ति में होना चाहिए। अत: हमारी कार्यसमिति को आवश्यक कदम उठाकर पूरे मजदूर वर्ग को इन पतनोन्मुख नीतियों के विरुद्ध लामबन्द करना चाहिए।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं चेतावनी के रूप में यह बात कहना चाहूंगा कि संपूर्ण रूप में इन परिस्थितियों के गर्भ में अनेक खतरे समाये हुए हैं।

लोकतांत्रिक तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों की संभावना से इकार नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारी नीतियों में साम्राज्यवाद को महत्वपूर्ण भूमिका सौंप दी गयी है। इसका उत्तर संगठित संघर्ष के रूप में दिया जाना चाहिए।

संपादक मंडल

एम. के. पंधे (चेयरमैन)
पी. के. गांगुली (कार्यकारी सम्पादक)
मनोरंजन राय, नीरेन घोष
एम. एम. लारेंस, विमल रणदिवे, रंजीत बसु